

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुंदरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:-1

देहरादून: दिनांक 17 फरवरी, 2017

विषय:- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(PMKSY) Per Drop More Crop घटक की
वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु राज्यांश धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 तथा संख्या 965/XXVII(1)/2016 दिनांक 19 अगस्त 2016 एवं आपके पत्र संख्या:-759/केन्द्रपोषित योजना/2016-7 दिनांक 14 फरवरी, 2017 तथा शासनादेश संख्या-2222/XVI-I/16/5(7)/2013t.c के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत(PMKSY) Per Drop More Crop घटक हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष सामान्य, अनुसूचित जाति एवं जनजाति मदों में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश धनराशि निम्न सारणीनुसार आपके निर्वतन पर कम्प्यूटर आई-डी सहित रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹लाख में)

क्रमांक	मद संख्या	राज्यांश
1	सामान्य	41.21686
2	अनुसूचित जाति	9.386
3	अनुसूचित जनजाति	1.55923
	योग	52.1621

(रूबावन लाख सोलह हजार इक्कीस मात्र)

- (1) उक्त प्राविधानित धनराशि का व्यय करते समय शासनादेश संख्या-2457/XV-I/16/5(7)2013T.C, दिनांक-23 नवम्बर, 2006 में निहित समस्त प्राविधानों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (2) योजनान्तर्गत अवमुक्त उपरोक्त राज्यांश धनराशि को भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय अनुपात (केन्द्रांश एवं राज्यांश) के अनुसार ही नियमानुसार अवमुक्त किया जाय।

(2)

- (3) उक्त धनराशि का व्यय अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश धनराशि के सापेक्ष निर्धारित प्रतिशत अनुपात में चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष, योजना की गार्डिलाइन एवं समस्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (4) उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में यदि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं से सम्बन्धित योजनाओं का भी समावेश किया गया हो, तो इस सम्बन्ध में धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि सम्बन्धित सभी औपचारिकताएँ यथा योजना/कार्य की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो, तथा डी0पी0आर0 टी0ए0सी0, ई0एफ0सी0, नियोजन विभाग से परिव्यय की उपलब्धता इत्यादि औपचारिकताएँ पूर्ण हैं।
- (5) उक्त धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-847/XXVII(1)/2016, दिनांक-26 जुलाई, 2016, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2010 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (6) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
- (7) निर्माण कार्यों के लागत व वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल 2012 के सम्बन्धित प्रस्तरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।
- (9) निदेशक उद्यान उक्त धनराशि प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित योजना के नोडल अधिकारी को समुचित प्रक्रियानुसार सम्बन्धित बैंक खाते अथवा अन्य में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (10) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-29, 30 एवं 31 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूक्ष्म सिचाई मिशन योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुंदरम)
सचिव।

संख्या- २०५ /XVI(1)/17/5(7)/13TC, तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 2- निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- राज्य योजना आयोग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 9- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी०एन० उप्रेती)
उप सचिव